

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण रि
आ

अपील संख्या 9/2023

1. परमेश्वरी पुत्री स्व० नौरंग पत्नि बुद्धराम, जाति जाट, निवासी कुल्हरियो का बास, तहसील र
जिला झुंझुनूं (राज०)
2. मणी पुत्री स्व० नौरंग पत्नि जयकरण, जाति जाट, निवासी भोजासर, तहसील मण्डावा, जिल
(राज०)

बनाम

1. पालाराम
2. चुन्नीलाल
3. पूर्णसिंह
4. महेश कुमार

पुत्रगण स्व० नौरंग, जाति जाट, निवासीगण रसोड़ा, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं (रा
---रेस्पो

प्रथम अपील अ०धा० 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रथम अपील खिलाफ आदेश तह
(भू०अ०) झुंझुनूं बाबत नामान्तरकरण संख्या 99 ग्राम रसोड़ा तत्कालीन तहसील झुंझुनूं हाल
मण्डावा आदेश दिनांक 20.06.1989

उपस्थित:-

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट- अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री किशोर कुमार जांगिड/श्री श्रवण सिंह, एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट्स सं० 1 व 3 की ओर
3. श्री सुनिल कुमार, एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट्स सं० 2 व 4 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 27

उक्त विषयक अपील विद्वान तत्कालीन तहसीलदार झुंझुनूं हाल तहसीलदार मण्डावा व
दिनांक 20.06.1989 नामान्तरकरण सं० 99 वाके कस्बा रसोड़ा के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्र
अन्तर्गत दफा 5 मि०अ० एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा०दी० पर बहस सुनी गयी। अ
निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत दफा 5 मि०अ० एवं प्र
अन्तर्गत धारा 96 जा०दी० स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट्स के अनुसार अपील इस प्रकार
कि ग्राम रसोड़ा में एक नौरंग नामक व्यक्ति पैदा हुआ। उक्त नौरंग का देहान्त दिनांक 04.02.
हुआ। नौरंग की पत्नि का देहान्त दिनांक 03.03.2018 को हुआ। नौरंग के चार पुत्र रेस्पोडेन्ट
पुत्रियां अपीलान्ट्स पैदा हुईं। इस प्रकार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के मुताबिक
वारिस अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स हुये। जमीन गत ख०न० 56/2 तादादी 26 बीघा ख
रकबा 6.58 बिश्वा व गत ख०न० 129 तादादी 7 बीघा कुल 26 बीघा 15 बिश्वा ख
लगायत 325 व 346 सरहद मौजा ग्राम रसोड़ा स्थित है। उक्त आराजी का टिनेट अधी
रेस्पोडेन्ट्स का पिता नौरंग रहा और उत्तराधिकार में उक्त आराजी के खातेदारी राईट्स बहिस्
अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स को प्राप्त हुये। अदालत मातहत ने नौरंग के देहान्त होने
आराजियात के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 99 बहक रेस्पोडेन्ट्स दिनांक 20.06.1989 को
से स्वीकार किया। उक्त विरासत नामान्तरकरण से अपीलान्ट्स प्रभावित है। उक्त ना
अपीलान्ट्स के हितो के विपरीत है। इस कारण अपीलान्ट्स की ओर से यह अपील नीचे लिख
पेश है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर बहस बाबत नामान्तरकरण संख्या 99 ग्रा
खिलाफ कानून न्याय व पत्रावली है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर

वारिसान की जांच नहीं की है और बिना वारिसान की जांच किये उपरोक्त नामान्तरकरण स्वीकार है। अपीलान्ट्स नौरंग की पुत्रियां होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नौरंग की वारिसान विरासतन नामान्तरकरण संख्या 99 अपीलान्ट्स व रेस्पोजेन्ट्स के हक में बहिस्सा बराबर स्वीकृत चाहिये था जो नहीं कर अदालत मातहत ने तथ्य व विधि की भूल की है। अदालत मातहत द्वारा 135 (1) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नामान्तरकरण स्वीकृत करने से उत्तराधिकारियों की जांच नहीं की गई है। आदेश जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। आदेश जैर बहस केवल यह दर्ज किया गया है कि "कॉलम संख्या 11 स्वीकार किया जाता है" इस प्रकार वारिसान जांच नहीं की गई है। अपीलान्ट्स नामान्तरकरण जैर बहस संख्या 99 ग्राम रसोड़ा दिनांक 20.06.1989 से प्रभावित हैं उक्त नामान्तरकरण अपीलान्ट्स के हितों के विपरीत स्वीकृत किया गया है। इस अपीलान्ट्स प्रभावित पक्षकार की हैसियत से यह अपील प्रस्तुत कर रही है। अतः अपील पेश निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश नामान्तरकरण संख्या 99 ग्राम रसोड़ा दिनांक 20.06.1989 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अदालत मातहत नौरंग के वारिसान की जांच कर विरासत नामान्तरकरण की कार्यवाही करे।

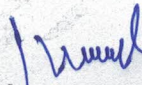
उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपीलान्ट्स की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर न देकर बिना अपीलान्ट्स के पिता की मृत्यु होने पर उक्त नामान्तरकरण अकेले रेस्पोजेन्ट्स के स्वीकृत किया है। अदालत मातहत ने राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 121 की जांच नहीं की है। वारिसान की जांच नहीं की है और बिना वारिसान की जांच किये उपरोक्त नामान्तरकरण स्वीकार किया है। अपीलान्ट्स नौरंग की पुत्रियां होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नौरंग की वारिसान है। विरासतन नामान्तरकरण संख्या 99 अपीलान्ट्स व रेस्पोजेन्ट्स के हक में बहिस्सा बराबर स्वीकृत करना चाहिये था जो नहीं कर अदालत मातहत ने तथ्य व विधि की भूल की है। अदालत मातहत द्वारा धारा 135 (1) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पहले उत्तराधिकारियों की जांच नहीं की गई है। आदेश जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। आदेश जैर बहस के केवल यह दर्ज किया गया है कि "कॉलम संख्या 11 स्वीकार किया जाता है" इस प्रकार वारिसान की जांच नहीं की गई है। अपीलान्ट्स नामान्तरकरण जैर बहस संख्या 99 ग्राम रसोड़ा दिनांक 20.06.1989 से प्रभावित हैं उक्त नामान्तरकरण अपीलान्ट्स के हितों के विपरीत स्वीकृत किया गया है। इस कारण अपीलान्ट्स प्रभावित पक्षकार की हैसियत से यह अपील प्रस्तुत कर रही है। अतः अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश बाबत नामान्तरकरण संख्या 99 ग्राम रसोड़ा दिनांक 20.06.1989 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अदालत मातहत नौरंग के वारिसान की जांच कर विरासत नामान्तरकरण की कार्यवाही करे।

बहस के दौरान वकील रेस्पोजेन्ट्स सं० 1 व 3 ने प्रा०प० राज० सरकार को नियुक्त किये जाने व प्रा०प० प्रारम्भिक आपत्ति का पेश कर हुए वकील अपीलान्ट्स के विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण में नामान्तरकरण सं० 99 वाके ग्राम रसोड़ा तहसीलदार झुंझुनू द्वारा तस्दीक किया गया है जिसे अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया कि अपील में आवश्यक पक्षकार थे। दूसरी ओर अपील आदेश दिनांक 20.06.1989 के पेश काफी देरी से पेश की गई है। अपील इतनी अधिक देरी से पेश करने का कोई युक्त कारण नहीं बताया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारीज फरमाई जावे।

बहस के दौरान वकील रेस्पोजेन्ट्स सं० 2 व 4 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलान्ट्स के हितों के विपरीत प्रार्थना पत्र 96 जा०दी० एवं प्रा०प० दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करने में कोई ऐतरा

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि वाके ग्राम ग्राम रसोडा के कम में नामान्तरकरण सं० 99 दिनांक 20.06.1989 में अपीलान्ट्स जो कि स्व० नौरंग की पुत्रिय उनके हक से वंचित किया गया है। विरासतन नामान्तरकरण में पुत्रियों को उनके हक नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम अदालत मातहत द्वारा भरे गये नामान्तरकरण 99 दिनांक 20.06.1989 वाके ग्राम रसोडा को त्रुटिपूर्ण मानते हैं। अतः वकील रेस्पोजेन्ट के प्रार्थना पत्र राज० सरकार को पक्षकार नियुक्त किये जाने व प्रा०प० प्रारम्भिक आपत्ति किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत को इन निर्देशों प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वारिसान की पूर्ण जांच कर पक्षकारान् को साक्ष्य पेश करने के समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारि मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फ़ैसल हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल०एस०
जिला कलेक्टर
झुझुन